भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2357

10 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

डी-कार्बोनाइजेशन की दिशा में कदम

2357. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:
श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस्पात क्षेत्र में डी-कार्बोनाइजेशन और संसाधन दक्षता में सुधार करने की दिशा में कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)**

(क) और (ख): इस्पात क्षेत्र में अकार्बनीकरण (डी-कार्बोनाइजेशन) और संसाधन दक्षता में सुधार लाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाये गए कदम निम्नानुसार हैं:-

(1) इस्पात मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्यबलों की सिफारिशों के अनुरूप ''ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप एंड एक्शन प्लान'' नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट इस्पात क्षेत्र का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है, इस्पात क्षेत्र के अकार्बनीकरण के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा करती है तथा इसके लिए रणनीति, कार्य योजना और रूपरेखा तैयार करती है।

(2) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तैयार किया है। इस्पात मंत्रालय इस मिशन में एक हितधारक है और इस मिशन के तहत वर्टिकल शाफ्ट में 100% हाइड्रोजन का उपयोग करके डारेक्ट रिड्यूस आयरन (डीआरआई) का उत्पादन करने के लिए दो पायलट परियोजनाएं और कोल/कोक खपत को कम करने के लिए मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन का उपयोग करते हुए एक पॉयलट परियोजना प्रदान की है।

(3) कच्चे माल के रूप में इस्पात स्क्रैप का उपयोग उत्सर्जन को 58% तक कम करता है। तैयार की गई इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 में इस्पात मंत्रालय द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मोटरयान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम सितंबर, 2021 में इस्पात क्षेत्र में स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

जारी...2/-

(4) जनवरी, 2010 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।

(5) राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन के अंतर्गत प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना द्वारा इस्पात उद्योग ऊर्जा खपत को कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

(6) इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में ऐसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर जोर दिया गया है जो पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान के साथ प्रभावी और कुशल घरेलू संसाधनों और परिष्कृत औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक उच्च-स्तरीय और विशेष इस्पात के लिए अनुकूल हैं।

******